



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240461  
CG-DL-E-22112022-240461

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 741]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का. नि. 832(अ).— केंद्रीय सरकार, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 382(अ), 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“11. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ;

12. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ;

13. राष्ट्रीय पुलिस विभाग ;

14. विनियामक, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 2 के खंड (चक) के अधीन यथा परिभाषित ;

15. विदेशी व्यापार महानिदेशक ;
16. विदेश मंत्रालय ;
17. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ;
18. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में फा.सं.11/2/2009-एडी.ई.डी., तारीख 29 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित विशेष अन्वेषण टीम ;
19. राष्ट्रीय आसूचना गिड ;
20. केंद्रीय सतर्कता आयोग ;
21. रक्षा आसूचना अभिकरण ;
22. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ;
23. सेना आसूचना ;
24. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के उपनियम (2) या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1950 (1950 का 37) के उपबंधों के अधीन नियुक्त जांच प्राधिकारी और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसमर्थन के साथ नियुक्त कोई अन्य प्रारंभिक जांच प्राधिकारी ;
25. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ।”

[फा.सं.पी-12011/8/2020-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्रा निदेशक मुख्यालय

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 382(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 609(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2020 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

**G.S.R. 832(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 382(E), dated the 27<sup>th</sup> June, 2006, namely:-

In the said notification, after serial number (10) and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

- “(11) National Investigating Agency;
- (12) Serious Fraud Investigation Office;
- (13) State Police Department;
- (14) Regulator, as defined under clause (fa) of rule 2 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;
- (15) Director General of Foreign Trade;
- (16) Ministry of External Affairs;

- (17) Competition Commission of India;
- (18) Special Investigation Team constituted, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, *vide* number F.No.11/2/2009-Ad.E.D. dated the 29<sup>th</sup> May, 2014;
- (19) National Intelligence Grid;
- (20) Central Vigilance Commission;
- (21) Defence Intelligence Agency;
- (22) National Technical Research Organisation;
- (23) Military Intelligence;
- (24) An inquiry authority appointed under sub-rule (2) of rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850) and any other preliminary enquiry authority appointed with concurrence of the Central Vigilance Commission, by the Disciplinary Authority, with the prior approval of the Central Government;
- (25) Wildlife Crime Control Bureau.”

[F.No. P-12011/8/2020-ES Cell-DOR]  
SHASHANK MISRA, Dir. Headquarter

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 382(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 1<sup>st</sup> October, 2020.